



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-आ.-25092020-221963

CG-MH-E-25092020-221963

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 377]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942

No. 377]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

### महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 8 सितम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/24/2014-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद् द्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास की कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणी की दर संरचना की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, करता है।

### महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास

—

आवेदक

### गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितंबर, 2020 के 7 वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) द्वारा डीपीटी की कांडला भूमि की दर संरचना की वैधता के विस्तार के लिए दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. डीपीटी की कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणी के पट्टा किराये पिछली बार 13 नवंबर, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा संशोधित किये गए थे। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित पट्टा किरायों को 01 जनवरी, 2014 से पूर्व व्यापी प्रभाव दिया गया था और पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2018 तक की वैधता निर्धारित की गई थी। डीपीटी को हमारे 05 नवंबर, 2018 के पत्र के द्वारा संशोधित दरों की अधिसूचना में विलंब से बचने के लिए डीपीटी भूमि के किरायों के संशोधन का प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद 14 अगस्त, 2019 को अनुस्मारक भी भेजा गया।

2.2. डीपीटी की कांडला भूमि 'ए' से 'जी' श्रेणी के पट्टा किराये की मौजूदा दर संरचना की वैधता का विस्तार, डीपीटी के अनुरोध पर, पिछली बार 20 फरवरी, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा उसकी समाप्ति की तारीख से 31 जून, 2020 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, डीपीटी द्वारा यथावांछित, किया गया था। उक्त आदेश में, डीपीटी को कांडला भूमि दर संरचना का संशोधित प्रस्ताव 15 मार्च, 2020 तक दायर करने का निदेश दिया गया था।

2.3. इस पृष्ठभूमि में, डीपीटी ने 04 मार्च, 2020 के अपने पत्र के द्वारा और तत्पश्चात् 20 मार्च, 2020 के ईमेल द्वारा किये गये निवेदन के संदर्भ में कांडला स्थित कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणी और गांव वीरा से जंगी (लवण भूमि और स्थिक भूमि के सिवाय) के 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक कि अवधि के लिये की दर संरचना के संशोधन का प्रस्ताव दायर किया। डीपीटी के प्रस्ताव को निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्रयोक्तायों/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिये परिपत्रित किया गया। इस मामले में 26 जून, 2020 को संयुक्त सुनवाई हो चुकी है।

3.1. इसी बीच डीपीटी ने 23 जून, 2020 के अपने पत्र के द्वारा डीपीटी भूमि के पट्टा किरायों के संशोधन के लिये डीपीटी के 20 मार्च, 2020 के ईमेल द्वारा किये गये प्रस्ताव के संदर्भ में आगे और स्थिति स्पष्ट करते हुए यह निवेदन किया है कि प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव को परामर्शी प्रक्रिया के लिये लिया गया है 26 जून, 2020 को हुई संयुक्त सुनवाई में बताया गया था कि 01 जनवरी 2019 से लागू होने वाली दरों को अंतिम रूप देने में अभी और समय लगेगा। अतः डीपीटी ने मौजूदा दरों की वैधता का विस्तार और 6 महीने के लिये अर्थात् 31 दिसम्बर, 2020 तक या संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, करने का अनुरोध इस शर्त पर किया है कि संशोधित दर को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जायेगा।

3.2. डीपीटी के प्रस्ताव को निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार संबंधित प्रयोक्तायों/प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिये परिपत्रित किया गया है। डीपीटी को प्रयोक्तायों/प्रयोक्ता संगठनों की टिप्पणियों का उत्तर देना होगा। इस मामले में 26 जून, 2020 को वीडियो कानफ्रेंसिंग के जरिये संयुक्त सुनवाई हो चुकी है। संयुक्त सुनवाई प्रक्रिया के हवाले से कुछेक प्रयोक्तायों/प्रयोक्ता संगठनों को इस प्राधिकरण को अपनी टिप्पणियां देने के लिये एक समाह का समय दिया गया और उनकी प्रति डीपीटी को भी भेजने का अनुरोध किया गया ताकि वे उन पर अपना उत्तर दे सकें। अतः इस मामले के अपनी अंतिमता तक पहुंचने में अभी और समय लग सकता है।

3.3. उक्त स्थिति को देखते हुए और चुंकि कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणी के पट्टा किरायों की मौजूदा दरों की वैधता का विस्तार और 6 महीने के लिए अर्थात् 31 दिसम्बर, 2020 तक या डीपीटी द्वारा दायर प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, तक करता है।

4.1. सरकार द्वारा जारी भू-नीति दिशानिर्देश 2014 (जिसके आधार पर डीपीटी की कांडला भूमियों की 'ए' से 'जी' श्रेणियों की दर संरचना नवंबर, 2014 में निर्धारित किये गए थे) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये तब तक 2% प्रति वर्ष की वृद्धि के अधीन होंगे जब तक इस प्राधिकरण द्वारा उनका संशोधन नहीं कर दिया जाता। इस प्राधिकरण द्वारा नवंबर 2014 में अनुमोदित आदेश में भी इस संबंध में यह शर्त विशिष्ट रूप से दी गई है। यह

एमओएस द्वारा जारी संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2014 में भी दी गई है। चूंकि वर्तमान दर संरचना को जब तक इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं कर दिया जाता तब तक और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 2% की वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी और 2% वार्षिक वृद्धि डीपीटी के 'ए से जी' श्रेणियों के लिए कांडला भूमि की दर संरचना में विस्तारित वैधता अवधि में भी लागू रहेगी।

4.2. तथापि, इस संबंध में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान पट्टा किरायों का विस्तार एक अंतरिम व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर किये गये प्रस्ताव के आधार पर 'ए से जी' श्रेणी के लिए कांडला भूमि के लिए निर्धारित किये जाने वाले पट्टा किरायों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना पड़ेगा, जैसा डीपीटी ने अनुरोध किया है।

5. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से यह प्राधिकरण कांडला भूमि की 'ए से जी' श्रेणी की मौजूदा दरों की वैधता को उनकी समाप्ति की तारीख से और 6 महीने के लिए अर्थात् 31 दिसम्बर, 2020 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये गये प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./231/2020-21]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 8th September, 2020

**No.TAMP/24/2014-KPT.**—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of rate structure of Kandla lands for categories 'A to G' of Deendayal Port Trust as in the Order appended hereto.

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### Case No.TAMP/24/2014-KPT

Deendayal Port Trust

---

Applicant

### ORDER

(Passed on this 7<sup>th</sup> day of September 2020)

This case relates to a proposal filed by Deendayal Port Trust (DPT) for extension of the validity of the rate structure for Kandla lands of DPT.

2.1. The lease rental for the Kandla lands for categories 'A to G' of DPT was last revised vide our Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014. The revised lease rental was implementable with retrospective effect from 01 January 2014 and valid for a period of five years, i.e. up to 31 December 2018. Since the validity of revised lease rental was to expire on 31 December 2018, DPT was, vide our letter No.TAMP/24/2014-KPT dated 05 November 2018, requested to expedite filing its proposal to avoid delay in notification of revised rates. This was followed by reminder letter dated 14 August 2019.

2.2. The validity of the existing rate structure for the Kandla lands for categories 'A to G' of DPT was extended from time to time and was last extended, based on the request of DPT, vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 20 February 2020 from the date of expiry till 30 June 2020 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier as sought by DPT. In the said Order, DPT was directed to file its proposal for revision of rate structure of Kandla land by 15 March 2020.

2.3. In this backdrop, the DPT vide its letter dated 04 March 2020 and subsequent submission via email dated 20 March 2020 has filed a proposal for revision of rate structure of Kandla Lands at Kandla for categories 'A to G' and village Veera to Jungi (excluding Salt land and SPIC land) for the period from 01 January 2019 to 31 December 2023. The proposal of DPT has been circulated to the concerned users/ user organisations for their comments as per the prescribed consultation process. The Joint hearing in this case was held on 26 June 2020.

**3.1.** In the meantime, the DPT, vide its letter dated 23 June 2020 has referring to the proposal filed by the DPT vide its email dated 20 March 2020 for revision of lease rent of DPT land and bringing out the position that its proposal is taken up for consultation process by the TAMP and the joint hearing dated 26 June 2020 has stated that finalization of rates applicable with effect from 1 January 2019 will take some more time. Hence, DPT has requested to extend the validity of existing rates for further 6 months i.e. till 31 December 2020 or till the date of effect of notification of revised lease rentals, whichever is earlier, subject to the condition that revised rates will be applicable with retrospective effect.

**3.2.** The proposal of DPT for revision of lease rent of the port land has been circulated to the users/ user organisations for their comments as per the prescribed consultation process. The DPT has to respond on the comments of the users / user associations. A joint hearing in this case was held on 26 June 2020 through video conferencing. Flowing from the joint hearing proceeding, a few users/ user associations have been given one week's time to furnish their comments/ submission to TAMP with a copy endorsed to DPT to respond thereon. Hence, it will take some more time for this case to mature for finalisation.

**3.3.** In view of above position and since the validity of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' expired on 30 June 2020, this Authority extends the validity of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' for further period of 6 months i.e till 31 December 2020 or till the date of effect of notification of revised lease rentals based on tariff proposal filed by the DPT, whichever is earlier.

**4.1.** The Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government (based on which the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT has been fixed in November 2014) stipulates that the lease rentals approved by the Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by the Authority. The Order approved by the Authority in November 2014 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the amended Land Policy Guidelines, 2014 issued by the Ministry of Shipping. Since the existing Rate structure already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by the Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT.

**4.2.** However, in this regard, it is relevant here to mention that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Kandla lands for categories 'A to G' based on the proposal filed by the DPT in this regard may have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

**5.** In the result, and for the reasons given above, this Authority extends the validity of the existing rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT from the date of its expiry till 31 December 2020 or the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal filed by the DPT, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./231/2020-21]